have been helped by entrepreneurs in imparting technical know-how, solving marketing problems and financial assistance; and

(b) what steps Government propose to take to direct big industries to encourage small scale industries to solve the unemployment problem in rural areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) During the year 1977-78, more than 3000 small scale industrial units were acting as ancillaries and sub-contractors to 66 public sector enterprises. During the same period, supplies of parts and components, assemblies about worth Rs. 78 crores were made by small scale units to the aforesaid public sector enterprises. According to the guidelines issued by the Bureau of Public Enterprises, the public sector undertakings assist their ancillery units in imparting technical-knowhow and assist them in procuring necessary financial assistance and raw-materials from the concerned institutional sources. As far as the large undertakings in the private sector are concerned, there is no regular system of monitoring the assistance provided by them to small scale units which are acting as their ancillaries. However, Government have now set-up 16 sub-contracting exchanges through out the country which are instrumental in establishing contacts between large and small scale units and help in promoting sales of products and services from the small sector.

(b) The Bureau of Public Enterprises has issued on May 9th, 1978 detailed guidelines to public sector enterprises to promote small scale industries as ancillaries. There are, however, no specific instructions in this regard which are applicable to rural areas exclusively. Wherever new, large and medium small scale units are established in rural areas and backward areas, all efforts are made to establish small scale ancillary industries to these units in these areas.

पुलिस द्वारा संवाददाताओं पर हमले

1454. श्री एस0 एस0 सोमानी :
श्री सरत कार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में चिकमगलूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस के लाठी-चार्ज से न केवल भारतीय पत्रकार बल्कि कुछ विदेशी पत्रकार भी शिकार हुये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सकार को इस बारे में विदेशों से भी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मण्डल) (क) से (ग). इस सम्बन्ध में टाइम मैगजिन मण्डल) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में टाइम मेगजिन के न्यूयार्क कार्यालय ने वाशिंगटन में भारतीय दूतावास से सम्पर्क किया था। कर्नाटक सरकार से तथ्यपूर्ण रिपोर्ट भेजने के लिये निवेदन किया गया है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

Confirmation of Employees on Deputation

1455. SHRI G. S. REDDI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) number of employees who have been confirmed or are being confirmed on the posts of deputation/ad-hoc nature under the Ministry of Industry; and

(b) whether such confirmation are against the recommendations of the Department of Personnel and Administrative Reforms?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) and (b). The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the House.

दर्शन में परिवहन यूनिटों के कार्यकरण की जांच

14 6. श्री टी0 ए0 नेगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 19 जुलाई, 6978 के अतारांकित

प्रश्न संख्या 579 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन के परिवहन यूनिटों से सम्बद्ध मामलों के बारे में कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है;

(ख) अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में कितना समय लगाने की संभावना है;

(ग) क्या इस बारे में दिल्ली दूरदर्शन के तत्कालीन स्टेशन डायरेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस घोटाले में कितने राजपत्रित अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जबकि सात व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां चल रही हैं ।

(ख) विभागीय कार्यवाहियां अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की होने के कारण दीर्घकालिक प्रक्रिया है । यद्यपि जांच पड़ताल को शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं तो भी कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं दी जा सकती ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस मामले में अन्तर्निहित राजपत्रित अधिकारियों की संख्या पांच है ।

हिन्दी कर्मचारी तथा सरकारी प्रयोजनों के लिये हिन्दी का विकास

1457. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में कितने हिन्दी अधिकारी, आशुलिपिक और टाइपिस्ट कार्य करते हैं; और

(ख) सरकारी कामकाज के लिये हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आशा मालिति): (क) उद्योग मंत्रालय में 5 हिन्दी अधिकारी 8 हिन्दी आशुलिपिक तथा 13 हिन्दी टाईपिस्ट हैं ।

(ख) मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाये जाने के संबंध में उठाए गए कदमों, सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के विषय में मार्गदर्शन करने तथा परामर्श देने के लिये हिन्दी सलाहकार-समिति का गठन करना, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का बनाया जाना, अंग्रेजी के शब्दों के हिन्दी पर्याय तथा वाक्यांशों की संग्रह पुस्तिका का सभी संबंधितों कर्मचारियों में वितरण करना तथा हिन्दी न जानने वाले अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों का हिन्दी भाषा हिन्दी स्टेनोग्राफी तथा टाइपिंग सीखने के लिए भेजा जाना शामिल है ।

Self sufficiency in Defence Equipment

1458. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether our country has achieved sufficiency in certain categories of defence equipment; and

(b) if so, particulars of those equipments?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) and (b). The country is self-sufficient in respect of a wide range of defence equipment and stores. We are very largely self-sufficient in the field of small arms, ammunition and field guns, and have achieved varying and increasing extent of indigenisation in respect of more sophisticated equipment and stores, including combat aircraft; warships; armoured and other vehicles; field guns; radar and communication equipment and other electronic equipment; heavy earth movers, tank-trailers and recovery vehicles; missiles and rockets; chemicals and propellants; etc. Progressively the indigenous content of Defence equipment and stores has been increasing, Unrelenting efforts continue to promote speedy indigenisation of Defence requirements, with priority given to more critical needs.

Taking over of Cement distribution by States

1459. SHRI YAMUNA PRASAD SHASTRI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the names of States and Union Territories where cement distribution has been taken over by the respective Governments from October, 1978;

(b) the steps taken by Central Government to check irregularities being committed in the distribution of cement as also its sale at more than the